



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122020-223452  
CG-DL-E-04122020-223452

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 2020/अग्रहायण 12, 1942

No. 620]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 2020/AGRAHAYANA 12, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2020

सं. 44/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 751(अ).**—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट, जिनकी चौड़ाई 600 मिमी से 1250 मिमी और 1250 मिमी से ऊपर हो और जिनका गैर वास्तविक प्रयोग किया जाता हो तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 7219 के अंतर्गत आते हों, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 61/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 11 दिसम्बर, 2015, जिसे सा.का.नि. 955(अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 52/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 24 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1327(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिनपश्चात् जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आकलन और उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा

क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिनपश्चात् जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है), के नियम 23 के अनुपालन में प्रारम्भिकीकरण अधिसूचना सं. 7/18/2020-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितम्बर, 2020, जिसे दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I, खंड-1, में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना में उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से निम्नलिखित संशोधन करती है यथा:-

### सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 61/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 [सा.का.नि. 955(अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 2015]	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:- “3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 31 जनवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।”
2.	अधिसूचना सं. 52/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 [सा.का.नि. 1327(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2017]	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:- “4. पैराग्राफ 3 में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 31 जनवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।”

[फा. सं. 354/87/2009-टीआरयू (पार्ट-V)]

जे. एस. कंधारी, उप सचिव

### नोट:-

1. प्रधान अधिसूचना सं. 61/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को सा.का.नि. 955(अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।
2. प्रधान अधिसूचना सं. 52/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1327(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd December, 2020

**No. 44/2020 -Customs (ADD)**

**G.S.R. 751(E).**—Whereas, the designated authority, *vide* initiation notification No. 7/18/2020-DGTR, dated the 30th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th September, 2020 has initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm and above 1250 mm of non-bonafide usage” falling under tariff heading 7219 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, originating in or exported from, the People’s Republic of China, Republic of Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and the United States of America imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/2015-Customs (ADD), dated the 11th December, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 955(E), dated the 11th December, 2015 and notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 52/2017-Customs (ADD), dated the 24th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1327(E), dated the 24th October, 2017 and has requested for extension of the said anti-dumping duties in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 61/2015 – Customs (ADD), dated the 11th December, 2015 [G.S.R. 955(E), dated the 11th December, 2015]	In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: - “3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 31st January, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier.”.
2.	Notification No. 52/2017 – Customs (ADD), dated the 24th October, 2017 [G.S.R. 1327(E), dated the 24th October, 2017]	In the said notification, after paragraph 3 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: - “4. Notwithstanding anything contained in paragraph 3, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force

		up to and inclusive of the 31st January, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier.”.
--	--	---

[F. No. 354/87/2009-TRU (Pt. V)]

J. S. KANDHARI, Dy. Secy.

**Note: -**

1. The principal notification No. 61/2015-Customs (ADD), dated the 11th December, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 955(E), dated the 11th December, 2015.
2. The principal notification No. 52/2017-Customs (ADD), dated the 24th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1327(E), dated the 24th October, 2017.